अगर आप जीत जाओ तो खुश हो जाओ और हार गए तो समझदार।
– अज्ञात

लोकतंत्र को झटका

देर-सबेर बाहर यह चर्चा होनी ही है कि आखिर यह कैसा लोकतंत्र है जिसमें किसी समस्या की ओर ध्यान खींचना भी जुर्म समझा जाता है! क्या नागरिकों को इतना भी हक नहीं कि वे देश के मुखिया से सीधा संवाद कर सकें?

नवीन

मॉब लिंचिंग की घटनाओं से चिंतित होकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने वाले 49 कलाकारों–बुद्धिजीवियों पर बिहार की एक अदालत में राजद्रोह का केस दर्ज होना भारतीय लोकतंत्र पर एक बड़ा धब्बा है। अधिकार और स्वतंत्रता को लेकर अक्सर पूरी दुनिया में भारतीय जनतंत्र की मिसाल दी जाती है। भीड़ की हिंसा पर चिंता जताने वालों को इस तरह पहली नजर में आरोपी मान लेना एक जनतांत्रिक समाज के रूप में हमारी छवि को भारी नुकसान पहुंचाएगा। देर–सबेर बाहर यह चर्चा होनी ही है कि आखिर यह कैसा लोकतंत्र है जिसमें किसी समस्या की ओर ध्यान खींचना भी जुर्म समझा जाता है!

क्या नागरिकों को इतना भी हक नहीं कि वे देश के मुखिया से सीधा संवाद कर सकें? बीती जुलाई में इतिहासकार रामचंद्र गुहा, फिल्मकार मणि रत्नम, अनुराग कश्यप और श्याम बेनेगल, अभिनेता सौमित्र चटर्जी, अभिनेत्री अपर्णा सेन और गायिका शुभा मुध्दग्गल समेत कला–संस्कृति से जुड़ी 49 हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मुस्लिमों, दलितों और अन्य कमजोर तबकों के खिलाफ जारी भीड़ की हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा था कि ऐसे मामलों में जल्द से जल्द सख्त सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। अच्छा होता कि सरकार इस विषय में अपनी सक्रियता से उन्हें अवगत कराती और ऐसी घटनाओं को रोकने में उनका सहयोग मांगती।

...लेकिन सरकार की तरफ से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। उलटे बिहार के मुजफ्फरपुर में एक वकील ने इन लोगों के खिलाफ दायर एक याचिका में आरोप लगाया कि अपने पत्र से इन्होंने प्रधानमंत्री और देश की छवि को धूमिल किया और अलगाववादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। अगस्त में दायर इस याचिका पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद बीते गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज हुई है जिसमें पत्र लिखने वालों पर राजद्रोह, उपद्रव और शांति भंग करने के इरादे से धार्मिक भावनाओं को आहत करने संबंधी धाराएं लगाई गईं हैं। इस पर देश भर में बवाल हुआ तो बिहार के डीजीपी ने सफाई दी कि बिहार सरकार का इस मामले से कोई लेना–देना नहीं है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया है। याचिका डालने वाले सज्जन नामचीन हस्तियों के विरुद्ध जनहित याचिकाएं दायर करते रहे हैं। अब तक वे अमिताभ बच्चन, रितिक रोशन, अभिषेक बच्चन, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ भी याचिकाएं दायर कर चुके हैं। जाहिर है, सवाल याचिका दायर होने पर नहीं, स्थानीय अदालत द्वारा इसे स्वीकार कर लेने पर है कि ऐसा करते हुए क्या संविधान के तकाजों को ध्यान में रखा गया है? लोकतंत्र में आलोचना या असहमति की थोड़ी–बहुत जगह अब तक जुडिशरी की सक्रियता की वजह से ही बची हुई है। इधर एक तबके में यह खतरनाक सोच जड़ जमा रही है कि सरकार या प्रधानमंत्री की आलोचना करना देशद्रोह है।

आत्मघाती है आलस्य

धर्म-दर्शन

श्री सुधांशु जी महाराज श्रीमदभगवदगीता ने कर्मयोग के बारे में जितना व्याख्यायित किया है, उतना और किसी ग्रंथ ने नहीं। कर्म की गम्भीरतम व्याख्या, वह भी भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य वाणी से। गीता का तीसरा अध्याय तो कर्मयोग की ढेरों उच्चस्तरीय व्याख्याओं से भरा हुआ है। गीतानायक ने लोक के वासियों को कर्म करने के लिए सदा प्रेरित किया। उन्होंने चाहा कि कर्मो में असंग रहे, कर्मकर्ता निसंग रहे, वह निष्काम भाव से कर्म करे। इसकी प्रेरणा श्रीकृष्ण ने महाबली अर्जुन के माध्यम से दुनिया को दी। उन्होंने कहा कि हमारा कर्म यज्ञ बन जाये, हवन बन जाये, अग्निहोत्र बन जाय। प्रभु श्रीकृष्ण कहते हैं– परोपकारी कर्म हो हमारा। अपना कर्म सेवा बन जाये, भक्ति बन जाय। हमारे कर्म से स्वार्थ निकल जाये, भगवान ने इसके लिए विविध–विधि प्रेरणायें दीं।

संपादकीय

रिजर्व बैंक का संकेत

भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते रेपो रेट में लगातार पांचवीं बार कटौती करते हुए उसे 5.15 फीसदी पर ला दिया, जो पिछले 9 वर्षों में सबसे कम है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक देश के सभी व्यापारिक बैंकों को लोन देता है। खास बात यह है कि पिछली कटौतियों का ज्यादातर फायदा बैंकों तक ही रह गया था, लेकिन अभी कई बैंकों का उधारी रेट रेपो रेट से जुड़ जाने से यह आम ग्राहकों तक पहुंच सकता है। बाजार में सस्ता कर्ज पहुंचने की गुंजाइश पर शेयर बाजार को उत्साहित होना चाहिए था लेकिन हुआ उलटा। रिजर्व बैंक की घोषणा के बाद शेयर बाजार में अच्छी–खासी गिरावट दिखी।

इसकी वजह रही ब्याज दर में कटौती के साथ ही जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान में की गई कतरब्योंत। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 6.9 फीसदी से घटा कर 6.1 फीसदी कर दिया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार का कहना है कि 6.5 फीसदी तक की सालाना विकास दर हासिल कर लेना अब भी मुमकिन है जबकि सरकार सात फीसदी का लक्ष्य हासिल करने का दावा कर रही है। लेकिन इन दावों से हटकर देखें तो हालात मुश्किल ही दिखते हैं। ढहती ग्रोथ रेट को संभालने में सबसे बड़ी बाधा यह है कि सरकार अब भी समस्या पर अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर पा रही। एक्सपोर्ट का माहौल तो जल्दी सुधरने वाला है नहीं, ऐसे में कंपनियां अपना उत्पादन तभी बढ़ाएंगी जब उन्हें घरेलू बाजार में अपने माल के खरीदार नजर आएंगे। इस लिहाज से दीर्घकालिक रणनीति किसानों की आमदनी और कम पगार वाली नौकरियों की तादाद बढ़ाने की ही हो सकती है। तात्कालिक कदमों की बात करें तो लगभग तैयार खड़ी हाउसिंग परियोजनाओं और छोटे–छोटे गैप्स की वजह से लंबित पड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करके उन्हें उत्पादक स्थितियों में लाना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

...भारतीय संस्कृति और परंपरा में ऐसे कृत्यों के लिए कोई स्थान नहीं है, न ही वह इनको किसी तरह से जायज ठहराती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारतीय समाज इधर इस बीमारी से ग्रस्त हो गया है।

मॉब लिंचिंग पर चिंता

बसंत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मॉब लिंचिंग एक पश्चिमी निर्मिति है, देश को बदनाम करने के लिए भारत के संदर्भ में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। विजयादशमी के मौके पर नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 'लिंचिंग' शब्द की उत्पत्ति भारतीय लोकाचार से नहीं हुई। इस तरह की घटनाओं से संघ का कोई लेना–देना नहीं है और इन्हें रोकना हर किसी की जिम्मेदारी है। कानून–व्यवस्था की सीमा का उल्लंघन कर हिंसा की प्रवृत्ति समाज में परस्पर संबंधों को नष्ट कर अपना प्रताप दिखाती है। यह प्रवृत्ति हमारे देश की परंपरा नहीं है, न ही हमारे संविधान में यह है। कितना भी मतभेद हो, कानून और संविधान की मर्यादा में रहें। संघ प्रमुख ने जो कहा है वह अपनी जगह सही है। भारतीय संस्कृति और परंपरा में ऐसे कृत्यों के लिए कोई स्थान नहीं है, न ही वह इनको किसी तरह से जायज ठहराती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारतीय समाज इधर इस बीमारी से ग्रस्त हो गया है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लोग जिस तरह की क्रूरता दिखा रहे हैं वह किसी भी सभ्य समाज के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में भीड़ ने एक दबंग परिवार के उकसावे पर दो बच्चों को खुले में शौच करने के कारण पीट–पीटकर मार डाला। इसी तरह झारखंड के खूंटी जिले में गोहत्या के शक में भीड़ ने एक अपाहिज को मार डाला। कुछ दिनों पहले बच्चा चोरी के शक में देश के कई इलाकों में लोगों पर हमले हुए।

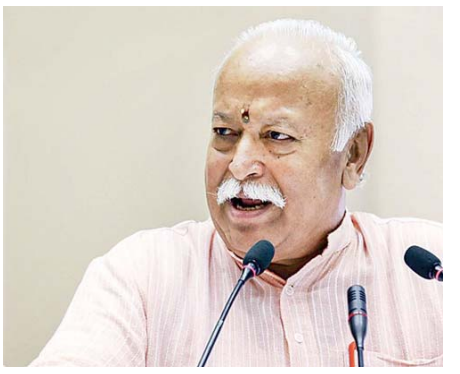

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कई बार मॉब लिंचिंग की कड़ी निंदा कर चुके हैं और राज्य सरकारों से ऐसी घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कड़ी टिप्पणी की है। लेकिन इन सबके बावजूद ऐसी घटनाएं होती ही जा रही हैं तो इससे यही पता चलता है कि हमारी कानूनी एजेंसियां ऐसी घटनाओं को लेकर पर्याप्त गंभीरता नहीं दिखा पाई हैं। जनता के एक हिस्से के साथ ही कानून–व्यवस्था से जुड़े लोगों में भी कहीं न कहीं यह बात घर कर गई है कि लिचिंग कुछ हद तक जायज है। हाल ही में पुलिस के बीच कराए गए एक सर्वे से पता चला कि पुलिसकर्मी भी गोहत्या के आरोपियों की मॉब लिंचिंग को कोई गलत बात नहीं मानते। सवाल यह है कि समाज में इस सोच ने आखिर कैसे जड़ जमा लिया? संघ प्रमुख आगे इस पर कुछ और प्रकाश डाल सकते हैं। सत्तारूढ़ दल के कुछ लोगों द्वारा दिए गए परोक्ष संरक्षण ने लिंचिंग के आरोपियों का मनोबल बढ़ाया है। बीमारी के इस हिस्से का इलाज सरकार ही कर सकती है। मोहन भागवत मॉब लिंचिंग को लेकर चिंतित हैं और इसे भारतीय संस्कृति के लिए घातक मानते हैं तो उन्हें आरएसएस और इसके आनुषंगिक संगठनों के जरिए इसके खिलाफ अभियान छेड़कर लोगों को जागरूक बनाना चाहिए।

आज का इतिहास

1733 फ्रांस ने रोम के खिलाफ जंग का ऐलान किया था।
1756 क्लाइव राईस कोलकाता पर पुन: कब्जे के लिए नौ सौ यूरोपीय व पंद्रह सौ भारतीय सैनिकों के साथ रवाना हुए।
1842 दूसरे अफगान युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटेन ने जीत का दावा किया।
1859 अर्जेन्टीना में गृहयुद्ध भड़का।
1911 चीन में डॉ. सनयात सेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने मंचू वंश का शासन उखाड़ फैंका।
1938 नाजी जर्मनी ने सुदेतनलैंड चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया।
1963 इटली में एक बांध टूटने से 18 लोग मारे गए।
1967 क्यूबा के क्रांतिकारी चेग्वेवारा बोलीविया में मारे गए।
1970 दो नकाबपोश व्यक्तियों ने क्यूबेक कनाडा के श्रममंत्री पियरेलापोर्टे का अपहरण कर लिया।

अपना ब्लॉग

राफेल हमें बचाएगा, और राफेल को नींबू !

आज राफेल की पूजा हो गयी। यह पूजा फ्रांस के एक एयरबेस पर सम्पन्न हुई। यह अलग बात है कि पूजा आज हुयी है और राफेल मिलना शुरू होगा अगले साल। यह विमान दुनियाभर के उत्कृष्ट विमानों में अपना स्थान रखता है। इसकी कीमत, इसके ऑफसेट पार्टनर, कुछ महत्वपूर्ण शर्तो में संशोधन को लेकर विवाद है, पर विमान की गुणवत्ता मे संदेह नहीं है। आज रक्षामंत्री जी ने राफेल का पूजन किया। पूजन परंपरागत रूप से हुआ। नींबू भी नजर उतारने के लिये पहियों के पास रखा गया था। दुनिया की आधुनिकतम तकनीक से बने राफेल को भी एक अदद नींबू की जरूरत पड़ती है, यह ज्ञान भी दुनिया को आज मिला। पूजा तो आस्था से जुड़ी है। हम सब तो जब परीक्षा हॉल में इम्तहान के लिये प्रश्नपत्र लेते थे, तो उसे पहले माथे से छूआते थे। गणित के पर्चे के साथ तो, यह मैं भी करता था। पर माथे से छुआने के बाद भी नम्बर अच्छे नहीं आते थे। काम नहीं आया कभी माथे से छुआना। काम तो पढ़ाई ही आयी। पर मन ही नहीं लगता था, गणित पढ़ने में। आज तक यह समझ नहीं पाया कि यह एक्स्ट्रा 2एबी क्या बला है। इस कारण, गणित में कमजोर था और अब भी हूँ।